श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, अभी प्रति बच्चे पर प्रारंभिक शिक्षा में लगभग 9.50 रुपये और माध्यमिक शिक्षा में करीब 11.50 रुपये खर्च आता है। जहाँ तक आपने जो यह बताया है कि इसका रेश्यो 60:40 है और कुछ जो हिमालयी तथा पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनमें यह रेश्यो 90:10 के हिसाब से है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो सीधे केन्द्रशासित प्रदेश हैं, वहाँ यह शत-प्रतिशत है। अब राज्यों को पर्याप्त राशि सीधे जाती है, जो कि पहले नही जाती थी। माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि राज्यों को उस समय जो अंश जाता था और आज जो अंश जाता है, उसमें बहुत अंतर है। इस तरह, राज्यों को और पोषित किया जा रहा है, सशक्त किया जा रहा है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, मैं आदरणीय माथुर जी से सहमत हूँ कि मिड-डे मील का कार्यक्रम जिस मंशा से चालू किया गया था, वह मंशा अभी तक पूरी नही हो पाई है। इसमें आपका एक लक्ष्य यह था कि इससे उनका एनरॉलमेंट बढ़ेगा, बच्चे स्कूल में आएँगे और दूसरा, इसकी वजह से उनको न्यूट्रिशन प्राप्त होगा। जहाँ तक न्यूट्रिशन पार्ट की बात है, तो मुझे नही लगता कि आज तक कभी इस बात का मूल्यांकन किया गया है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ने आए, जिनको मिड-डे मील मिली, उनके शरीर में पोषण का स्तर कहाँ तक पहुँचा।

सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि क्या किसी भी लेवल पर इस बात का कोई मूल्यांकन हुआ है कि जिस किस्म का पोषण बच्चों को दिया जा रहा है, उससे उनकी ग्रोथ पर सकारात्मक रूप से कितना फर्क पड़ा है तथा आगे उसके लिए और क्या किए जाने की आवश्यकता है?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, यह बिल्कुल सही है कि नामांकन बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया था। बच्चा सुदृढ़ हो सके, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसका भी समय-समय पर विश्लेषण होता है। निश्चित रूप से यदि मिड-डे मील नही होती, तो बहुत कम नामांकन होते और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता, यह बात एक सीमा तक संशोधित होकर सामने आई है।

श्री उपसभापति: प्रश्न संख्या 53.

Investments under National Digital Communications Policy, 2018

*53. SHRI A. MOHAMMEDJAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Digital Communications Policy, 2018 would draw investments worth US 100 billion dollars into the country's telecom sector in five years;

(b) whether it is also a fact that around US 16 billion dollars have already been announced by the private sector companies and Government *via* Universal Service Obligation Fund with a rough split of 65 per cent and 35 per cent respectively; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DHOTRE SANJAY SHAMRAO): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The National Digital Communications Policy 2018 (NDCP-2018) was notified on 22nd October, 2018 with a vision to support India's transition to a digitally empowered economy and society by fulfilling the information and communications needs of citizens and enterprises by establishment of a ubiquitous, resilient and affordable Digital Communications Infrastructure and Services. NDCP-2018 is a policy designed to further fulfil the larger objective of Digital India. The key objectives of the policy are provisioning of Broadband for all; creating 4 Million additional jobs in the Digital Communications sector; enhancing the contribution of the Digital Communications sector to 8% of India's GDP from ~ 6% in 2017; propelling India to the Top 50 Nations in the ICT Development Index of International Telecommunication Union (ITU) from 134 in 2017; enhancing India's contribution to Global Value Chains; and ensuring Digital Sovereignty. The policy *inter alia,* aims to attract investments of USD 100 Billion in the Digital Communications Sector.

(b) and (c) In order to achieve the strategic objective of provisioning of broadband for all, National Broadband Mission has been launched on 17th December, 2019. The Mission aims to attract investments from stakeholders of around US 100 billion dollars (Rs 7 Lakh Crore) out of which approximately 10% will be provided by Government through Universal Service Obligation Fund (USOF).

SHRI A. MOHAMMEDJAN: Respected Deputy Chairman, Sir, the National Digital Communication Policy, 2018 envisages investment worth 100 million US dollars into the country's telecom sector. But there is widespread apprehension about the recent Supreme Court ruling on the debt of existing telecom service providers.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief because time is limited.

SHRI A. MOHAMMEDJAN: Therefore, I would like to know from the hon. Minister the steps taken to allay the fear of the investors in telecom sector.

श्री धोत्रे संजय शामराव: सर, टेलीकॉम सेक्टर में हमारा जो "डिजिटल इंडिया प्रोग्राम" है, उसके लिए एक "नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, 2018" बनाई गई। उसके बाद, "राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान" दिनांक 17.12.2019 को लॉंच किया गया। इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं, उसकी डिटेल में मैं नही जा रहा हूँ, क्योंकि समय कम है।

सर, इन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला। उसमें करीब-करीब 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होगा, यानी उसमें सात लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें 70,000 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट है, वह USO Fund से किया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट ने भी कुछ निर्णय लिए हैं। जैसा कि उन्होंने ऑपरेटर के बारे में बोला, तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमने अभी एक डिसीजन यह लिया है कि टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर (टीएसपी) को या तो एक या दो वर्षों के लिए 2020-21 और 2021-22 को आस्थगित करने का विकल्प देगा। यह आस्थगित राशि टीएसपी द्वारा भुगतान की जाने वाली शेष किस्त में समान रूप से दी जाएगी। हमने अभी एक डिसीज़न यह लिया है कि जो spectrum usage charges है, उसकी पेमेंट के लिए हमने दो साल की deferment policy बनाई है।